बसंत पंचमी की शुभकामनाएं

दैनिक नईदुनिया

भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित

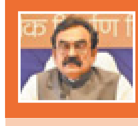
राजधानी... कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान केंद्रित करने की...

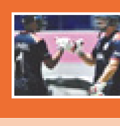
खेल... ओमान दौरे के लिए एंड्रीज गौस, स्टीवन टेलर और...

व्यापार... बजट के झटके से सेंसेक्स और निफ्टी ने गंवाई...

देश-विदेश... भारत ने मोस्ट वांटेड अर्श डल्ला पर कनाडा मेहरबान...

www.naiduniaonline.com

वर्ष- 78 (भोपाल : वर्ष 40 अंक 65, पृष्ठ 12) | रविवार 2 फरवरी 2025 | राजधानी संस्करण | कीमतः 3:00 रुपये

आम बजटः मध्यम वर्ग की मौज

» 12 लाख की आय तक कोई कर नहीं » कृषि और निवेश को प्रोत्साहन » बिहार को सौगात

नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने के साथ ही अर्थव्यवस्था को गति देने वाले चार इंजनों कृषि, एमएसएमई, निवेश तथा निर्यात को विशेष प्रोत्साहन देने के उपाायों करते हुए बिहार के लिए कई घोषणायें की है।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इसके साथ ही अब आयकर के लिए नया स्लैब जारी होगा जिसमें शून्य से चार लाख रुपये तक की आय पर शून्य कर, चार लाख रुपये से आठ लाख रुपये तक पांच प्रतिशत, आठ लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक 10 प्रतिशत, 12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 16 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत, 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये तक 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत आयकर लगेगा। बजट में वित्त मंत्री ने 12.75 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं और वेतनभोगियों के लिए शून्य कर के प्रावधान के साथ साथ किराये से प्राप्त पर आय और बुजुर्गों की ब्याज से आय पर टीडीएस की कटौती की सीमा बढ़ाने के उपाय किये हैं। उन्होंने एमएसएमई इकाईयों को नयी परिभाषा दी है जिसमें उनके निवेश और कारोबार की सीमा 2.5 गुना और दो गुना हो गयी है। श्रीमती सीतारमण ने शनिवार को संसद में तेलुगु कवि और नाटककार गुरजादा अप्पा राव की प्रसिद्ध पंक्ति, एक देश सिर्फ उसकी मिट्टी नहीं है, एक देश उसके लोग हैं को उद्धृत किया और सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करते हुए सबका विकास थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि उधार के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 34.96 लाख करोड़ रुपये और 50.65 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। शुद्ध कर प्राप्तियाँ 28.37 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष में उधार के अलावा कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 31.47 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से शुद्ध कर प्राप्तियां 25.57 लाख करोड़ रुपये हैं। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 47.16 लाख करोड़ है, जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 10.18 लाख करोड़ रुपये है। राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 2024-25 सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.8 प्रतिशत है जबकि बजट 2025-26 में जीडीपी का 4.4 प्रतिशत होने का अनुमान है। राजकोषीय समेकन को जारी रखने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हर साल राजकोषीय घाटे को इस तरह बनाए रखने का प्रयास करती है कि केंद्र सरकार का कर्ज जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घटता रहे और इसके लिए अगले छह वर्षों के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने विकसित भारत के सिद्धांतों को रेखांकित किया, जिसमें शून्य गरीबी, सौ प्रतिशत अच्छी गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा, उच्च गुणवत्ता वाली, सस्ती और व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच, सार्थक रोजगार के साथ सौ प्रतिशत कुशल श्रम, आर्थिक गतिविधियों में सत्तर प्रतिशत महिलाएँ और किसानों पर जोर दिया गया है। सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-2026 विकास को गति देने, समावेशी विकास को सुरक्षित करने, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने, घरेलू भावनाओं को ऊपर उठाने और भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयासों को जारी रखने का वादा करता है। बजट में गरीब, युवा, किसान और महिला पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव है। बजट का उद्देश्य भारत की विकास क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए कराधान, बिजली क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और नियामक सुधारों में परिवर्तनकारी सुधार शुरू करना है। बजट में कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को विकसित भारत की यात्रा में इंजन बताया गया है। सीतारमण ने कहा कि लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और मांग, विकसित भारत की यात्रा के प्रमुख स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग भारत के विकास को ताकत देता है और सरकार ने उनके योगदान को मान्यता देते हुए समय-समय पर शून्य कर स्लैब में बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नई कर संरचना मध्यम वर्ग के हाथों में अधिक पैसा देकर उपभोग, बचत और निवेश को काफी बढ़ावा देगी। बजट में किये गये प्रस्ताव के तहत एक लाख रूपए तक मासिक औसत आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। इससे मध्यमवर्ग परिवारों की आय व खपत में वृद्धि होगी। वेतनभोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा। बजट में किये गये इस प्रस्ताव से 24 लाख रुपये या उससे अधिक की वार्षिक आय वाले करदाताओं को 1.10 लाख रुपये की बचत होगी। हालांकि इससे सरकार का एक लाख करोड़ रुपये का राजस्व कम हो जायेगा। उन्होंने कहा कि बजट में राज्यों के साथ साझेदारी में देश के 100 जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, ताकि उत्पादकता बढ़ाई जा सके, फसल विविधीकरण को अपनाया जा सके, कटाई के बाद भंडारण को बढ़ाया जा सके, सिंचाई सुविधाओं में सुधार किया जा सके और दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाया जा सके। कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के माध्यम से कृषि में अल्प रोजगार की समस्या दूर करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम (शेष पेज 2 पर)

क्या-क्या हुआ सस्ता

36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटी,6 दवाओं पर ड्यूटी लिस्ट 5 फीसदी हुई , बुने हुए कपड़े, 37 दवाओं और 13 मरीज सहायता प्रोग्राम को छूट दी गई है, मेडिकल उपकरण भी सस्ते होंगे, मोबाइल फोन की कीमतों में भी गिरावट आएगी। मोबाइल फोन बैटरी के 28 सामान को मिली छूट, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बैटरी सस्ती होगी, चमड़े के सामान पर भी टैक्स कम किया गया है, जिससे वह सस्ता होगा, एलईडी और स्मार्ट फोन भी सस्ते होंगे, केंद्र सरकार ने 7 टैरिफ रेट्स को हटा दिया है, फ्रोजन फिश पेस्ट पर कस्टम ड्यूटी 30 फीसदी से घटकर 5 प्रतिशत हुई, इसके अलावा 12 जरूरी मिनरल्स, शिप बनाने के लिए कच्चे माल की कस्टम ड्यूटी पर भी अगले 10 साल तक के लिए छूट बढ़ा दी गई है। जिनसे लिथियम बैटरी, रिचार्जेबल बैटरी बनाई जाती है को भी सस्ता किया गया है।

क्या-क्या हुआ महंगा

तैयार कपड़ों की विभिन्न श्रेणियों के आयात पर शुल्क बढ़ाकर 20 प्रतिशत या 115 रुपये प्रति किलोग्राम (जो भी ज्यादा हो) कर दिया गया है। इसके अलावा इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दी गई है। इससे इनके दाम भी बढ़ेंगे।

बजट की मुख्य विशेषताएं

नई व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपये तक की आय (अर्थात पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर प्रति माह 1 लाख रुपये की औसत आय) पर कोई आयकर नहीं देना होगा । वेतनभोगी वर्ग के लिए, 12.75 लाख की वार्षिक आय तक कोई आयकर लागू नहीं है, क्योंकि वेतनभोगी वर्ग को ?75,000 का मानक कटौती लाभ उपलब्ध है। विभिन्न आय स्तरों पर स्लैब दर में परिवर्तन और छूट के कुल कर लाभ को उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है। नई व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाता को कर में 80,000 का लाभ मिलेगा (मौजूदा दरों के अनुसार देय कर का 100 प्रतिशत छूट प्राप्त होगा)। प्रभावी आयकर दर 0 प्रतिशत होगी।16 लाख की आय वाले व्यक्ति को कर में 50,000 का लाभ मिलेगा । देय प्रभावी आयकर दर सिर्फ 7.5न्न होगी। 18 लाख की आय वाले व्यक्ति को कर में 70,000 का लाभ मिलेगा। देय प्रभावी आयकर दर सिर्फ 8.8न्न होगी। 20 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को कर में 90,000 रुपये का लाभ मिलेगा। देय प्रभावी आयकर दर सिर्फ 10न्न होगी। 25 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को 1,10,000 रुपये का लाभ मिलेगा । प्रभावी कर दर सिर्फ 13.2प्रतिशत होगी 50 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को भी 1,10,000 रुपये का लाभ मिलेगा। प्रभावी कर दर सिर्फ 21.6 प्रतिशत होगी। इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का राजस्व छूट जाएगा। बजट 2025 में सबसे महत्वपूर्ण जोर बुनियादी ढांचे पर है। सरकार ने प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की है, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देना और पूरे देश में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। मुख्य हाइलाइट्स में शामिल हैं। डिजिटल क्रांति भारत के विकास की आधारशिला बनी हुई है। बजट 2025 में प्रौद्योगिकी और नवाचार की परिवर्तनकारी शक्ति को मान्यता दी गई है, तथा निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया है। एक बहुप्रतीक्षित सुधार कर प्रणाली का प्रस्तावित सरलीकरण है। बजट 2025 में व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों के लिए कर अनुपालन को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन की गई विभिन्न पहलों की रूपरेखा दी गई है । सरकार (शेष पेज 2 पर)

किसानों, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों सहित हर वर्ग की आकांक्षाएं होंगी पूरीः मोदी

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को आम नागरिकों को समर्पित बताते हुए कहा कि इस बजट से किसानों, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों सहित हर वर्ग की आकांक्षाएं पूरी होंगी और देश की विकास यात्रा भी तेज होगी।

श्री मोदी ने आम बजट 2025-26 पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि आज भारत के विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों के आकांक्षाओं का बजट है, ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि हमने कई सेक्टर युवाओं के लिए खोल दिए हैं। ये विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है, ये बजट प्रगति को कई गुना बढ़ाने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिलकुल उल्टा है। ये बजट, देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगा, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे।ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश (शेष पेज 2 पर)

बजट से उम्मीदें पूरी नहीं हुईः केजरीवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि उन्होंने अरबपतियों के कर्ज के संबंध में जो मांग की थी, वह वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में पूरी नहीं हुई, जिससे उन्हें दुख हुआ है।श्री केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा चंद अमीर अरबपतियों के क़र्ज़े माफ़ करने में चला जाता है। मैंने माँग की थी कि बजट में ये ऐलान किया जाए कि आगे से किसी अरबपति के क़र्ज़ माफ़ नहीं किए जाएँगे। इस से बचने वाले पैसे से मिडल क्लास के होम लोन और व्हीकल लोन में छूट दी जाए। किसानों के कर्ज़े माफ़ किए जायें।

विकसित भारत का सपना होगा साकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपना रिकॉर्ड लगातार आठवां केंद्रीय बजट पेश किया। बजट को लेकर भाजपा नेताओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है। भाजपा नेताओं ने बजट का स्वागत किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला बेहतरीन बजट है। इस बजट में समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। यह बजट युवाओं, गरीबों, किसानों, महिलाओं और समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने वाला है।

राजनाथ ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में रक्षा मंत्रालय को 6.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से लगभग 9.5 प्रतिशत अधिक है और रक्षा बलों का आधुनिकीकरण हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है।

केन्द्रीय बजट मध्यम वर्ग के लिए बड़ी सौगात : डॉ. यादव

भोपाल(काप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट 2025-26 विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कल्याणकारी, सर्व-स्पर्शी और समावेशी बजट देश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के समग्र विकास के साथ स्टार्ट-अप्स, इनोवेशन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते हुए, अंत्योदय की भावना और नवोन्मेष की नव-दृष्टि से परिपूर्ण है। डॉ. यादव ने कहा है कि श्रीमती सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट में 2025-26 में 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय को कर मुक्त करने का निर्णय अभिनंदनीय है। बीते एक दशक में श्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने समृद्धि के जो नए आयाम स्थापित किए हैं, उनमें देश के मध्यम वर्ग का परिश्रम और सामर्थ्य सम्मिलित है। श्री मोदी के मार्गदर्शन में लिया गया यह निर्णय मध्यम वर्ग की आशाओं और आकांक्षाओं को उड़ान देने के साथ उन्हें सशक्त बनाने में निर्णायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने देशवासियों के कल्याण और भारत को आत्मनिर्भर बनाने और मध्यम वर्ग को आयकर में राहत देने वाले क्रांतिकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री का प्रदेशवासियों की ओर से आभार माना।

आर्थिक संकट के समाधान के लिये बजट में कोई उपाय नहींः राहुल

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट 2025-26 को आर्थिक क्षेत्र में सरकार के वैचारिक दिवालियापन की संज्ञा देते हुये शनिवार को कहा कि बजट प्रस्तावों में अर्थव्यवसथा में सुधार के लिये कोई ठोस बात नहीं है। उन्होंने इस बजट को गोली के घाव को मरहम से ठीक करने जैसा प्रयास करार दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में कुछ भी नया नहीं था और बजट में तबाह हो रही अर्थव्यवस्था को संभालने के कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। इसमें जो कुछ भी कदम उठाने की कोशिश हुई है, वह गोली के घाव पर मरहम लगाने जैसा है। श्री गांधी ने अपनी बजट प्रतिक्रिया में कहा कि गोली के घावों के लिये एक बैंडेज-सहायता।

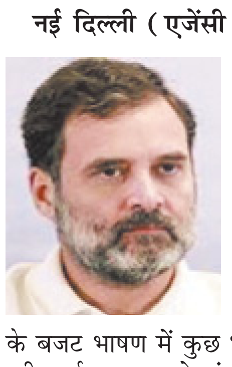

स्पेशल खबर *इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव पर बोले शाह...*

हमेशा मोदी के दिल में रहता है मध्यम वर्ग

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज केंद्रीय बजट 2025 में कर कटौती की सराहना करते हुए कहा कि मध्यम वर्ग हमेशा पीएम मोदी के दिल में है।

12 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले लोगों को पूरी छूट देने वाले टैक्स ब्रैकेट में बदलाव की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि यह मध्यम वर्ग की वित्तीय भलाई को बढ़ाने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगा। उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि

इस अवसर पर सभी लाभार्थियों को बधाई। शाह ने लिखा कि 12 लाख रुपये की आय तक शून्य आयकर। प्रस्तावित कर छूट मध्यम वर्ग की वित्तीय भलाई को बढ़ाने में काफी मदद करेगी। इस अवसर पर सभी लाभार्थियों को बधाई। उन्होंने कहा कि बजट-2025 विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है।

किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला और बच्चों की शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य से लेकर स्टार्ट अप, इनोवेशन और निवेश तक, हर क्षेत्र को समाहित करता यह बजट मोदी के आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप है। गृह मंत्री ने कहा कि विकसित भारत बजट 2025 किसान कल्याण की दिशा में मोदी सरकार के संकल्प का प्रतिबिंब है। बजट में 100 सबसे कम फसल उत्पादकता वाले जिलों में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की घोषणा से लगभग 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। साथ ही, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन व कपास उत्पादकता मिशन से किसानों की समृद्धि व पोषण सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।